

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर यूपी-112 द्वितीय चरण के तहत उच्चकृत पीआरवी को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। साथ ही उन्होंने वातानुकूलित हेलमेट का वितरण भी किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि यह कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की सात वर्ष की प्रक्रिया को नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का अभियान है।

उन्होंने कहा कि कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है। इसके लिए सुरक्षा और संरक्षा का बेहतर वातावरण होना चाहिए। सुरक्षा का वातावरण राज्य का दायित्व है। हमारी पुलिस इसका बखूबी निर्वहन करती है।

श्री योगी ने कहा कि पिछले सात वर्ष में यूपी पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी नई पहचान बनाई है, बल्कि यूपी को भी नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दो हजार सत्रह में यूपी, आबादी में देश का सबसे बड़ा राज्य और छठवीं अर्थव्यवस्था था। जैसे-जैसे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ तो यूपी देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा और अब तेजी के साथ देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं देंगे तो पुलिस बल पिछड़ जाएगा। ऐसा होने से सबसे खतरनाक असर सामान्य नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ेगा। जनता का विश्वास एक बार व्यवस्था से हटा तो उसे बहाल करने में लंबे समय तक कवायद करनी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रवेश किया है। यूपी ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि निवेश, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव पारदर्शी प्रक्रिया से पुलिस बल में पुलिस भर्ती की तो समुचित प्रशिक्षण भी कराया। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अनेक प्रयास हुए हैं। पहली बार यूपी पुलिस बल के लिए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है। जहां पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिये गये हैं। कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में निर्माणाधीन एवं नवीन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं तथा औद्योगिक कॉरीडोर और डिफेंस कॉरीडोर के विकास की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीते सात वर्ष में उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। दो हजार सत्रह तक सिर्फ दो एक्सप्रेस-वे वाले इस प्रदेश में आज छह एक्सप्रेस-वे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी सात वर्ष पहले की तुलना में लगभग दोगुने हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में नई पहचान मिल रही है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को आगामी दिसंबर माह तक आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाए ताकि प्रयागराज कुंभ दो हजार पच्चीस में देश-दुनिया के श्रद्धालुगण गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा का लाभ उठा सकें। श्री योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गोरखपुर, संतकबीर नगर आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर जनपद के लिए यह शानदार कनेक्टिविटी का माध्यम बनेगा।

उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जीवनरेखा बन चुके बुंदेलखंड एक्सप्रेस को चित्रकूट से जोड़ने के लिए कार्यवाही तेज की जाए। इसके लिए बजट भी जारी किया जा चुका है। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने में बहुत सहायक होगा। श्री योगी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे कवरेज को और विस्तार देने की आवश्यकता है। जेवर में विश्वस्तरीय एयरपोर्ट बन रहा है, इसे एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए, गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाए। इसी प्रकार, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे तक वाया फर्रुखाबाद एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ-साथ यह तीन नए एक्सप्रेसवे प्रदेश की तरक्की को तेज करने वाले होंगे। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए।

प्रदेश के परिषदीय स्कूल कल से खुल जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों का समय निर्धारित कर दिया है। स्कूल कल और उनतीस जून को सुबह साढ़े सात बजे से दस बजे तक खुलेंगे। एक जुलाई से स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय सुबह आठ बजे से दो बजे तक रहेगा।

कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार जिले के अंदर ही दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। कुल एक लाख चौतीस हजार परिषदीय स्कूलों में सत्ताईस हजार नौ सौ तिरानबे विद्यालय ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जिनमें पचास से भी कम विद्यार्थी हैं। अब छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार इन विद्यालयों में जो भी शिक्षक अधिक हैं, उनका दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरण किया जाएगा। इस संबंध में विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी ने निर्देश जारी कर दिये हैं।
